

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 43-एक/2005 - विरुद्ध आदेश दिनांक  
20-10-2004- पारित धारा - बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर -  
प्रकरण क्रमांक 14/1994-95 विविध

बाबूलाल पुत्र प्रेमलाल नाई  
ग्राम जोगनी तहसील देवसर  
जिला सीधी , म0प्र0

-----आवेदक

विरुद्ध

- 1- शिवफल 2- भवानी पुत्रगण लालमन नाई  
ग्राम करेला तहसील चितरंगी जिला सीधी
- 3- जबाहरलाल पुत्र लछनधारी बेशवार  
ग्राम जोगनी तहसील चितरंगी जिला सीधी
- 4- मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)  
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक ०१- ११ -2017 को पारित)

यह अपील बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 14/1994-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 20-10-2004 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।  
2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली दल क-1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके मांग की कि ग्राम जोगनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 13, 120, 125, 136, 163, 253, 254 कुल

किता ७ कुल रक्खा 1.460 हैक्टर के हिस्सा 1/2 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) का भूमिस्वामी रामप्यारे पुत्र बिन्द्रावन नाई है जिसके क्षारा उसके हित में बसीयत की गई है इसलिये उसका नामांतरण किया जावे। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 50 अ-६/१९८५-८६ पैजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 7-६-१९८६ पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध मक्तूलिया पुत्री वृन्दावन एंव जबाहर लाल पुत्र लक्षणधारी ने बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण क्रमांक ३२/८८-८९ अपील में पारित आदेश दिनांक २ मई १९९१ से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर ने ३१/८८-८९ अपील को ६-७-९५ को अदम पैरबी में निरस्त कर दिया गया, जिसका पुर्णस्थापन आवेदन आने पर प्रकरण क्रमांक १४/१९९४-९५ विविध पैजीबद्ध किया गया एंव पक्षकार के अनुपस्थित रहने के कारण आदेश दिनांक १४-५-९८ से पुर्णस्थापन आवेदन अमान्य किया गया। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर क्षारा प्रकरण क्रमांक १५७१-तीन/१९९८ एंव १५७८-तीन/१९९८ में पारित आदेश दिनांक २७-७-२००१ से बंदोवस्त आयुक्त के प्रकरण क्रमांक १४/१९९४-९५ विविध में पारित आदेश दिनांक १४-५-९८ एंव आदेश दिनांक २०-१०-२००४ निरस्त कर दिया तथा प्रकरण गुणदोष के आधार पर सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया, जिस पर बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर प्रकरण क्रमांक १४/१९९४-९५ विविध में आदेश दिनांक २०-१०-२००४ पारित किया एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली का आदेश दिनांक ७-६-८६ एंव बंदोवस्त अधिकारी सीधी के का आदेश दिनांक २ मई १९९१ निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के एक सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली के आदेश दिनांक 7-6-86, बंदोवस्त अधिकारी सीधी के के आदेश दिनांक 2 मई 1991 तथा बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर के आदेश दिनांक 20-10-2004 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जिस बसीयत के आधार पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली ने आदेश दिनांक 7-6-86 से बसीयतग्रहीता आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया है उसके परीक्षण पर बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर ने इस प्रकार अभिमत प्रकट किया है -

” बसीयतनामा पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। बसीयत साक्ष्य द्वारा सावित भी नहीं की गई। बसीयत सावित करना आज्ञापक है तथा विल उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 'ग' के अनुसार सावित की जाना चाहिये। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अधीन विहित शीति में सावित किये बिना विल सावित होना नहीं माना जावेगा। ”

बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर ने आदेश दिनांक 20-10-2004 में उपरोक्त के आगे विवेचित किया है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों को भी सूचना नहीं दी। हितबद्ध पक्षकार या अभिलिखित हितग्राही सठखातेदार, संयुक्त खातेदार, निकटतम वारिस, हित प्रतिनिधि, वैद्य प्रतिनिधि आदि को पूर्व सूचना दिये बिना और उनकी सुनवाई किये बिना इस्तहार विधिवत जारी किये बिना और हकदार की अनदेखी की गई कार्यग्राही अवैध एंव क्षर्त है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सिंगरोली द्वारा प्रकरण क्रमांक 50 अ-6/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 7-6-1986 में इस प्रकार की कमियों उजागर होने के आधार पर तथा बंदोवस्त अधिकारी सीधी द्वारा आदेश दिनांक 2-5-91 पारित करते समय उक्तानुसार कमियों को नजरबदाज कर दिये जाने के कारण बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 14/1994-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 20-10-2004 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रृटिपूर्ण पाकर निरस्त किये हैं। बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर का आदेश दिनांक 20-10-2004 बोलता हुआ आदेश Speaking Order है एंव आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके

हैं कि बंदोवस्त आयुक्त के आदेश दिनांक 20-10-2004 में किन कमियों का समावेश है जिसके कारण उसमें हस्तक्षेप किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर बंदोवस्त आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर क्षारा प्रकरण क्रमांक 14/1994-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 20-10-2004 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सार्थीन होने से निरस्त की जाती है।

  
(एस०एस०अली)

सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर